फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 25 प्रभात जयपुर, बुधवार 26 अगस्त, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

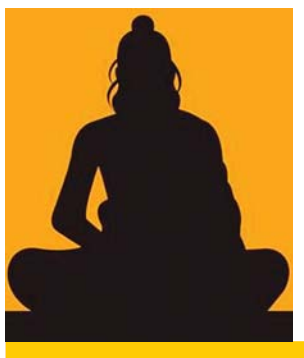

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

The Guru We No Longer Treat as One

The cost of that mismatch will not show up this year or next. It will show up a decade from now, in graduates who can clear an exam but struggle to hold a value, and by then, it will be too late to ask who was supposed to teach them

The Gentle Foundation of Melody and Emotion

प्र.मंत्री न तो संघ के सामने झुकना चाहते हैं और न ही ऐसी छवि चाहते हैं

इसीलिए संघ के जितने भी सुझाव आ रहे हैं, वे उन पर कोई निर्णय नहीं ले रहे

- बताया जाता है कि आरएसएस चाहता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस को संसदीय बोर्ड में शामिल किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री इसके पक्ष में नहीं हैं।
- अगर फड़नवीस को संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया तो अन्य मुख्यमंत्रियों को बोर्ड में शामिल करने की मांग उठ सकती है और प्रधानमंत्री मोदी संसदीय बोर्ड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को कदापि लेना नहीं चाहते हैं।
- यह भी कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री ने यह मांग मान ली तो अगली मांग गडकरी या राजनाथ सिंह को उपप्रधानमंत्री बनाने की हो सकती है। यही वजह है कि सभी निर्णय अधरझूल में हैं।
- सूत्रों का कहना है कि महत्वपूर्ण निर्णय मोहन भागवत की विदेश यात्रा से वापसी के बाद हो सकते हैं, जो अमेरिका, कैनडा व ब्रिटेन की यात्रा पर हैं और संघ की विचारधारा के लोगों से मिल कर भारत की स्थिति पर सलाह मशविरा कर रहे हैं।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अगस्त। नरेन्द्र मोदी सरकार इस समय असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है। लंबे समय से चर्चित केन्द्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल, मुख्यमंत्रियों के बदलाव, संसदीय बोर्ड के गठन और अन्य महत्वपूर्ण फैसलों को फिलहाल रोक दिया गया है।

इसकी मुख्य वजह आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) है।

आरएसएस अपनी विचारधारा और दृष्टिकोण के अनुरूप कुछ बदलाव और कुछ महत्वपूर्ण फैसले चाहता है। यही वह बिंदु है, जहां मामला अटक गया है।

प्रधानमंत्री न तो आरएसएस के सामने झुकना चाहते हैं और न ही ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वे संघ के दबाव में आ रहे हैं। यही कारण है कि वे आरएसएस की कई सिफारिशों को स्वीकार करने में हिचक रहे हैं।

एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, आरएसएस चाहता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को भाजपा संसदीय बोर्ड में शामिल किया जाए।

लेकिन प्रधानमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यदि फडणवीस को संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया तो इसके बाद अन्य मुख्यमंत्रियों को भी इसमें शामिल करने की मांग उठेगी।

इसके बाद यह सुझाव सामने आया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी संसदीय बोर्ड में शामिल कर लिया जाए।

इस सुझाव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह दोनों को नाराज कर दिया।

यदि मोदी इस मांग को स्वीकार करते हैं तो इसके बाद अगली मांग नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह में से किसी एक को उपप्रधानमंत्री बनाए जाने की हो सकती है।

यही वजह है कि फिलहाल सभी बड़े संगठनात्मक और राजनीतिक बदलावों को रोक दिया गया है।

सूत्रों का कहना है कि कई महत्वपूर्ण फैसले मोहन भागवत की अमेरिका यात्रा के बाद लिए जा सकते हैं। भागवत तीन देशों, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के दौरे पर जाने वाले हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बांके बिहारी मंदिर का चढ़ावा मंदिर के खाते में जमा हो

नई दिल्ली, 25 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से दिए जाने वाले दान के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि मंदिर में दान किया गया एक-एक पैसा भगवान के खजाने में जमा होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मंदिर के आधिकारिक वेबसाइट या दान

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर की प्रबन्धन समिति को चढ़ावा हासिल करने व हिसाब के लिये पारदर्शी सिस्टम बनाना चाहिये।

पेटियों के जरिए ये राशि सीधे मंदिर के खाते में जानी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मंदिर से जुड़ा कोई भी व्यक्ति मंदिर के खजाने में जमा होने से पहले चढ़ावे की राशि पर अपना अधिकार नहीं जता सकता है। उच्चतम न्यायालय ने मंदिर की प्रबंधन समिति को चढ़ावा हासिल करने और उसके हिसाब के लिए एक पारदर्शी सिस्टम स्थापित करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य गड़बड़ियों को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी प्रकार के चढ़ावे का उचित ढंग से हिसाब रखा जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मंदिर में दिया गया दान भगवान के लिए है।

अमेरिका और चीन के संबंध टकराहट के रास्ते पर

ईरान से ऑयल खरीदने वालों के लिए अमेरिका की नई नीति में अप्रत्यक्ष रूप से चीन को चुनौती दी गई है, क्योंकि ईरान के ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार चीन ही है

- हालांकि, अमेरिका ने अपनी इस नई नीति में ईरान से जुड़ी कंपनियों, जहाजों व लोगों को निशाना बनाया है, चीन की कंपनियों को नहीं। इससे लगता है कि वॉशिंगटन व्यापक आर्थिक टकराव शुरु किए बिना ही चीन पर दबाव बनाना चाहता है।
- यूएस-चीन इकोनॉमिक एंड सिक्युरिटी रिव्यू कमीशन के अनुसार, ईरान द्वारा निर्यात किए जाने वाले तेल का 90 प्रतिशत चीन खरीदता है, इससे ईरान को हर साल अरबों डॉलर की आय होती है और इस आय को कम करना चीन पर दबाव बनाए बिना संभव नहीं है।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अगस्त। अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने को लेकर चीन को चेतावनी दी है। इससे वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच एक नए आर्थिक टकराव की आशंका बढ़ गई है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने अभी तक चीनी संस्थाओं पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाने से परहेज किया है।

ईरान से तेल खरीदने वाले देशों के लिए अमेरिकी ट्रैज़री सैक्रेटरी स्कॉट बैसैंट की "आर्थिक डी-डे" (इकोनॉमिक डी-डे) की चेतावनी को मुख्य रूप से चीन के लिए माना जा रहा था, क्योंकि ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा चीन खरीदता है। फिर भी, अमेरिका के हाल के प्रतिबंधों में ईरान से जुड़ी कंपनियों, लोगों और जहाजों को निशाना बनाया गया, न कि चीन के बड़े वित्तीय संस्थानों को। इससे संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन व्यापक आर्थिक टकराव शुरू किए बिना बीजिंग पर दबाव बनाना चाहता है।

बैसैंट ने सोमवार को कहा, "हम जानते हैं कि वे कौन हैं। वे भी जानते हैं कि वे कौन हैं।" इससे संकेत मिला कि ईरान के साथ व्यापार जारी रखने वाले देशों को चेतावनी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी कड़ी कार्रवाई से पहले अपनी अपेक्षाएं बताने के लिए "शांत कूटनीति" का इस्तेमाल कर रहा है।

अमेरिका की इस रणनीति के लिए चीन सबसे बड़ी परीक्षा है। यू.एस.-चीन इकोनॉमिक एण्ड सिक्यूरिटी रिव्यू कमीशन के अनुसार, ईरान के निर्यात किए जाने वाले तेल का लगभग 90 प्रतिशत चीन खरीदता है। इससे ईरान को हर साल अरबों डॉलर की आय होती है। इसलिए ईरान की तेल से होने वाली आय को गंभीर रूप से कम करने की कोई भी कोशिश चीन से टकराव के बिना संभव नहीं है।

तथापि, चीन ने अमेरिकी दबाव को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि प्रतिबंध और दबाव की रणनीति मूल समस्याओं का समाधान नहीं करेगी, बल्कि इससे तनाव और बढ़ने का खतरा होगा।

लिन ने कहा, "चीन संबंधित घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केन्द्र सरकार ने चलाई स्पेशल ट्रेन "कांदा एक्सप्रेस"

प्याज़ के दामों में 59 प्रतिशत वृद्धि होने से चिंतित सरकार ने यह कदम उठाया है

- महाराष्ट्र के नासिक से चलने वाली यह ट्रेन दिल्ली, चेन्नई, कोच्चि, मदुरै और गुवाहाटी तक जाएगी।
- इस पहल के तहत सोमवार को 800 टन प्याज़ नासिक से दिल्ली भेजा गया था।
- सरकार बड़ी-बड़ी मंडियों में प्याज़ का स्टॉक भेज रही है, ताकि प्याज़ के खुदरा दामों में कमी की जा सके।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अगस्त। पिछले कुछ सप्ताह में प्याज की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बाद सरकार ने थोक और खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अपने "बफर स्टॉक" से प्याज़ की सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए विशेष रेल शुरू की गई है।

सरकार ने "कांदा एक्सप्रेस" की पहल करते हुए, महाराष्ट्र के नासिक से पांच प्रमुख शहरों-दिल्ली, चेन्नई, कोच्चि, मदुरै और गुवाहाटी तक रेल के जरिए प्याज़ भेजना शुरू कर दिया है।

ताजा हस्तक्षेप के तहत, सोमवार को नासिक के "लासलगांव" से 800 टन से अधिक बफर स्टॉक का प्याज़ दिल्ली भेजा जाएगा।

सरकार का तत्काल लक्ष्य प्रमुख मंडियों में बड़ी मात्रा में प्याज पहुंचाना है, ताकि थोक कीमतों में कमी आए। थोक दरों में स्थाई गिरावट आने से आगे चलकर खुदरा प्याज़ की कीमतों में भी कमी आने की उम्मीद है, खासकर दिल्ली-एनसीआर में।

प्याज़ की कीमतों में 59 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद सरकार ने बाजार में अपना हस्तक्षेप बढ़ा दिया है, हालांकि उसका कहना है कि देश में प्याज़ की कुल उपलब्धता फिलहाल पर्याप्त है।

प्याज़ की कीमतों में मौसमी उतार-चढ़ाव का असर उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है, क्योंकि अलग-अलग फसल चक्रों से आने वाली आपूर्ति में बदलाव होता रहता है। लेकिन केन्द्र सरकार का कहना है कि आने वाले महीनों में घरेलू मांग पूरी करने के लिए देश में प्याज़ का पर्याप्त भंडार मौजूद है।

सरकार बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अपने प्याज़

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्रीमी लेयर लागू करने के लिये दो साल का समय दें- केन्द्र सरकार

नई दिल्ली, 25 अगस्त। केन्द्र सरकार ने क्रीमी लेयर मामले में उच्चतम न्यायालय के 11 मार्च के फैसले को पिछली तारीख से लागू करने के लिए दो साल का समय देने की मांग की है। केन्द्र सरकार का कहना है कि

- सरकार का कहना है कि इस फैसले का असर सरकारी नौकरियों, सीनियॉरिटी, उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिलों पर पड़ सकता है।

इस फैसले का असर सरकारी नौकरियों, सर्विस और कैंसर आवंटन, सीनियरिटी, उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला और 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पर पड़ सकता है।

केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस ने सोच समझकर निर्णय लिया, सीजेपी के रूल्स को दूर से देखें व कुछ सीखें

इस नीति के तहत कांग्रेस ने अपनी राजनैतिक रैलियों का स्वरूप भी बदला है

- इस संबंध में पुणे में हुए राहुल गांधी के "छात्रों की गूंज" कार्यक्रम का उदाहरण दिया जा सकता है, जिसमें सिर्फ लड़कियों की समस्याओं पर फोकस किया गया था।
- राहुल गांधी ने कार्यक्रम में कहा, जंतर-मंतर के प्रदर्शनकारियों के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी का लड़के-लड़कियों के प्रति पक्षपात पूर्ण रूख था। जिस बात के लिए लड़कियों से माफी मंगवाई गई, उसके लिए लड़कों को कुछ नहीं कहा गया।
- कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सामान्यतौर पर युवा की बात करने से काम नहीं चलेगा। युवा लड़कों व युवा लड़कियों की समस्याओं और मुद्दों को अलग-अलग नज़रिए से देखना होगा।
- हालांकि, सीजेपी आंदोलन की शुरुआत में कांग्रेस ने जानबूझ कर इससे दूरी रखी, क्योंकि तब पार्टी को आशंका थी कि यह भाजपा द्वारा प्रायोजित अभियान हो सकता है और इसका लक्ष्य पेपर लीक व अयोध्या राम मंदिर की चढ़ावा चोरी से संबंधित कांग्रेस के अभियानों को कमज़ोर करना हो सकता है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अगस्त। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को 22 अगस्त को पुणे ले गए, जहां विशेष रूप से युवा महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतही तौर पर यह केवल कार्यक्रम के आयोजन से जुड़ा एक छोटा-सा फैसला लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह कांग्रेस के भीतर पिछले दो महीनों से चल रही बहस के नतीजे को दर्शाता है।

कार्यक्रम का प्रारूप भी महत्वपूर्ण था। छात्राओं ने हिंसा, आवाजाही पर पाबंदियां, घर की असमान जिम्मेदारियां, आर्थिक स्वतंत्रता की कमी और सुरक्षा के नाम पर लगाए जाने वाले सामाजिक नियंत्रण जैसे मुद्दों पर बात की।

राहुल गांधी ने इन शिकायतों को जंतर-मंतर के प्रदर्शनों से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी ने विशेष रूप से युवा महिलाओं द्वारा किये गये अभद्र भाषा के इस्तेमाल को "सांस्कृतिक झटका" बताया, लेकिन पुरुष प्रदर्शनकारियों के इसी तरह के व्यवहार पर कुछ नहीं कहा।

जेन ज़ैड के लोकप्रिय नारे "पितृसत्ता खत्म करो" (स्मैश पैट्रिआर्की) का इस्तेमाल करते हुए ,राहुल गांधी ने कांग्रेस को उन युवा महिलाओं के साथ खड़ा करने की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तरुण तेजपाल दो सप्ताह में सरेंडर करें

नई दिल्ली, 25 अगस्त। अपने सहयोगी से दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता तहलका के पूर्व पत्रकार तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस आलोक अराधे ने तरुण तेजपाल को दो हफ्ते में सरेंडर करने का

- सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 22 सितम्बर को।

आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

इस मामले की सुनवाई के दौरान, गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि अपने सहयोगी से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए तहलका के पूर्व पत्रकार तरुण तेजपाल को उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल करने के पहले सरेंडर कर देना चाहिए था। सुनवाई के दौरान तरुण तेजपाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि तरुण तेजपाल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान से व्यापार के कारण अमेरिका ने चार भारतीय कंपनियों को दंड के लिए चिन्हित किया है

क्या यह अमेरिका द्वारा भारत की संप्रभुता को चुनौती देना नहीं है

- ईरान को सैन्य युद्ध में झुकाने में असफल रहने के बाद अब अमेरिका अनुचित आर्थिक युद्ध का सहारा ले रहा है आर अन्य देशों को ईरान के खिलाफ अपने साथ आने के लिए मजबूर कर रहा है।
- अमेरिका के इस कदम ने मोदी सरकार को अटपटी स्थिति में डाल दिया है और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। देखना यह है कि मोदी सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।
- भारत की जिन चार कंपनियों पर प्रतिबंध लगे हैं, उन पर ईरान से पैट्रोलियम व पैट्रोलियम उत्पादों की खरीद, अधिग्रहण, बिक्री, परिवहन व बिक्री के आरोप लगाए गए हैं।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अगस्त। अमेरिकी विदेश विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के स्वीकृत नियमों और तौर-तरीकों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए, अमेरिका ने ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों का आयात करने वाली भारत स्थित चार कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह जानकारी अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है।

ईरान को युद्ध के मैदान में अपनी मनमानी के आगे झुकाने में बुरी तरह विफल रहने के बाद ट्रंप प्रशासन अब अनुचित आर्थिक युद्ध का सहारा ले रहा है। इसके तहत, वह स्वतंत्र देशों पर तेहरान के साथ व्यापार बंद करने का दबाव बना रहा है। संक्षेप में, अमेरिका अन्य देशों को ईरान के खिलाफ अपने युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहा है, जो उनकी संप्रभुता और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के अधिकार को चुनौती देता है।

अमेरिका के इस कदम ने एक बार फिर मोदी सरकार को असहज स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि नई दिल्ली अमेरिका द्वारा लगातार किये जा रहे अपमान को बिना किसी विरोध के स्वीकार करती रही है।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को "ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट" की घोषणा की। इसके तहत नए प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनका उद्देश्य ईरान के लिए आय के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। अमेरिका ने अन्य देशों से भी तेहरान के साथ आर्थिक संबंध समाप्त करने को कहा है और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

बेसेंट ने इसे ईरान की वित्तीय जीवनरेखाओं को काटने के लिए चलाया जा रहा अभूतपूर्व अभियान बताया। इससे उन संस्थाओं, जो देश, व्यवसाय या संगठन हो सकते हैं, पर सेकेंडरी सैंक्शंस का खतरा बढ़ गया है, जो तेहरान के साथ कारोबार जारी रखते हैं।

प्रतिबंधों की कार्रवाई का सामना करने वाली चार भारत स्थित कंपनिया में कस्टम्स ब्रोकर पोर्टईज़ पार्टनर्स एलएलपी भी शामिल है। इसके साझेदार इदरीसमिया अशरफमिया शेख और हरीश रामचंद्र रंगी भी कार्रवाई के दायरे में हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, इन लोगों ने ईरान से पेट्रोकेमिकल उत्पादों की कई खेपों के आयात में मदद की थी।

अन्य भारतीय कंपनियों में सदाशिव ओवरसीज़ लिमिटेड, पीपी सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक प्रशांत गर्ग और प्रकृतिस इन्फ्रा इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

विदेश विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार, शेख, रंगी और गर्ग भारतीय नागरिक हैं।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सदाशिव ओवरसीज़ ने विभिन्न कंपनियों से लगभग 6.9 करोड़ डॉलर मूल्य के ईरानी मूल के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया, जबकि पीपी सॉफ्टटेक और प्रकृतिस इन्फ्रा ने लगभग 2.5-2.5 करोड़ डॉलर मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'नीट प्रदर्शन की जांच समिति को पुनर्गठित करें'

नई दिल्ली, 25 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक याचिका का उल्लेख किया गया, जिसमें दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पुलिस की ज्यादतियों और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए बनी पांच

- सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश।

सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति के पुनर्गठन की मांग की गई है।

इस समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी हैं।

समिति के संयोजन पर आपत्ति जताते हुए कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)